<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2230

01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

हरित इस्पात का उत्पादन

2230. श्री प्रह्लाद जोशीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हरित इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है अथवा प्रोत्साहन देने का विचार है, जिसके उत्पादन से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): लोहा और इस्पात एक लाईसेंस मुक्त और नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) नामशः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और अन्य निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियां अपने इस्पात संयंत्रों के दक्षता पैरामीटरों में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे है, जिनमें विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी लाना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों वाले नये संयंत्रों की स्थापना करना भी शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने कम ऊर्जा खपत वाली स्वच्छ और ग्रीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जापान सरकार की सहायता से बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में मॉडल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को भी सुगम बनाया है। इस्पात मंत्रालय ने यूएनडीपी और अन्य की वित्त सहायता से गौण क्षेत्र में भी कम विद्युत खपत वाली ग्रीन प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन किया है ताकि इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 जारी की है जिसमें भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने, ऊर्जा के उपयोग में दक्ष बनाने और मूल्यवर्धन वाले इस्पात के उत्पादन पर बल देने के साथ उत्पादक को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और किफायती उत्पादक बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर भी सीधा असर पड़ेगा।

******